Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

कक्षा - 12

स्वतंत्र भारत में राजनीति

अध्याय - 6

लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट

भाग - 3

Satyaveer Yadav

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार

12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला

- न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा
- समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर चुनाव याचिका के मामले में
  - इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती तर्क – चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवा का इस्तेमाल किया गया।

इंदिरा गांधी अब कानूनन सांसद नहीं रहीं

- 6 माह की अवधि में सांसद निर्वाचित नहीं होती है तो प्रधानमंत्री नहीं रह सकती

24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय का इस फैसले पर आंशिक स्थगनादेश

- इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होगी तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी लेकिन वे लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती।

इ.गांधी

चुनाव

आरोप

राजनारायण चौधरी

आदर्श चुनाव आचार संहिता

30-90 days

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

संकट

- जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव बनाया।
- इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया।
- जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालना ना करें।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

आन्तरिक अशांति

राष्ट्रपति → F. A. अहमद

आपातकाल की घोषणा

आधी रात 25 जून 1975 को देश में गड़बड़ी की आशंका पर आपातकाल की घोषणा

संघीय ढांचा व्यावहारिक तौर पर निष्प्रभावी

सारी शक्तियां केन्द्र के हाथों में

तड़के सबेरे बड़े पैमाने पर विपक्षी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी







Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

RSS → 27 Sep. 1925 (विजयादशमी)

संस्थापक - डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार

मुख्यालय - नागपुर (MH)

जमात-ए-इस्लामी

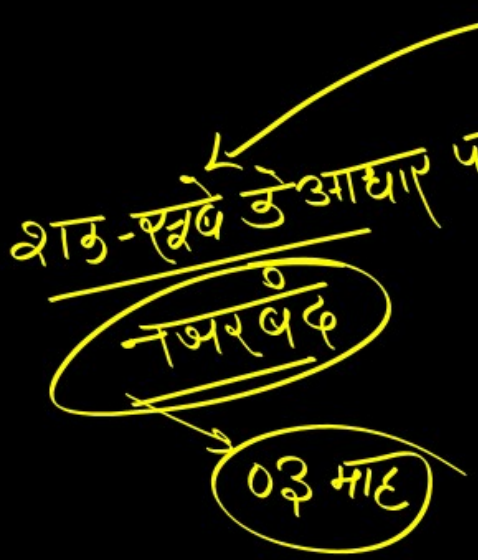
- 1941
- मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी

परिणाम

- प्रेस की आजादी पर रोक
- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध
  - सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मध्यनजर
- नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी
- धरना प्रदर्शन और हड़ताल की अनुमति नहीं

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



- सरकार ने निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया।
- आपातकाल के दौरान निवारक नजरबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गयीं।
- जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दे सकते थे।
- नागरिकों को उनकी गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक नहीं है - सरकार
- अनेक उच्च न्यायालयों के फैसले - आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गयी ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर सकती